आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
गुरुवार 11.09.2025
समय 1830

मुख्य समाचार :–

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की। श्री मोदी ने उत्तराखंड में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए देहरादून में समीक्षा बैठक की।

- केंद्र सरकार और एशियन विकास बैंक ने टिहरी झील क्षेत्र में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 126 दशमलव 4–2 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।

- नाबार्ड ने प्रदेश में शिक्षा और डेयरी विकास विभाग को अवसंरचना विकास के लिए 93 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी।

- चंपावत में ''पोषण भी–पढ़ाई भी'' अभियान के तहत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।

प्रधानमंत्री दौरा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज देहरादून में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के आपदा प्रभावित इलाकों में हुए नुकसान और राहत व पुनर्वास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। श्री मोदी ने उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों के लिए 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की। श्री मोदी ने आपदा राहत कार्यों में लगी केंद्र और प्रदेश सरकार की टीमों के सदस्यों से बातचीत कर उनसे जानकारी भी ली। प्रधानमंत्री को आज राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करना था, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका दौरा रद्द हो गया। गौरतलब है कि इस मॉनसून सीज़न में प्रदेश के कई जिलों– विशेषकर उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर और टिहरी में भारी बारिश और भूस्खलन से सामान्य जन–जीवन प्रभावित हुआ है।

समझौता हस्ताक्षर

एशियाई विकास बैंक– एडीबी और केंद्र सरकार ने टिहरी झील क्षेत्र में सतत और जलवायु–लचीले पर्यटन के माध्यम से ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए 126.42 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और एडीबी के भारत में प्रभारी अधिकारी काई वेई येओ ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। सुश्री मुखर्जी ने कहा कि एडीबी ऋण, प्रदेश सरकार की उस नीति का समर्थन करता है, जिसके तहत राज्य को एक विविधतापूर्ण, सभी मौसमों में पर्यटन के लिए उपयुक्त पर्यटन स्थल के रूप में तैयार करना है और टिहरी झील को विकास के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। श्री येओ ने कहा कि यह परियोजना एक जल–विद्युत झील के आसपास स्थायी पर्यटन के लिए एक मॉडल प्रस्तुत करती है, जिसमें रोजगार सृजन, आय में विविधता लाने और जलवायु दृढ़ता बनाने के लिए बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया गया है। परियोजना के तहत प्रदेश के सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील और आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में से एक टिहरी में कई कार्यक्रमों होंगे। इसका उद्देश्य बेहतर पर्यटन योजना, उन्नत बुनियादी ढाँचे, बेहतर स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन और आपदा तैयारी के माध्यम से 87 हजार से अधिक निवासियों और हर वर्ष आने वाले 27 लाख आगंतुकों को लाभान्वित करना है।

स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान

बागेश्वर जिले में महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य को लेकर ''स्वस्थ नारी–सशक्त परिवार'' अभियान 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक लेकर अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान जिलेभर में स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं और परामर्श उपलब्ध कराए जाएंगे।

स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. सुनीता टम्टा ने बताया कि अभियान में महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ एनीमिया, टीबी, मुख, स्तन व गर्भाशय ग्रीवा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ ही स्वच्छता और पोषण संबंधी जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे।

नाबार्ड स्वीकृति

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक– नाबार्ड ने ग्रामीण अवसंरचना विकास को सुदृढ़ करने के क्रम में प्रदेश सरकार को आर.आई.डी.एफ़ के तहत करीब 93 करोड़ रुपए की तीन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। शिक्षा विभाग को बागेश्वर जिले में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय और चमोली जिले में राजकीय इंटर कॉलेज सिल्पाटा के निर्माण के लिए 44 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक स्वीकृत किए गए हैं। इन परियोजनाओं से पहाड़ी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक शैक्षिक सुविधाएँ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध होगा, जिससे इन क्षेत्रों में शिक्षा के अवसरों का दायरा और व्यापक होगा। वहीं, डेयरी क्षेत्र में 48 करोड़ 21 लाख रुपए से अधिक की लागत से ऊधमसिंह नगर जिले के सितारगंज में आधुनिक 10 एम.टी क्षमता के

मिल्क पाउडर संयंत्र, पांच हजार लीटर क्षमता के आइसक्रीम प्लांट और दो एम.टी क्षमता के बेकरी यूनिट स्थापित किए जाएंगे। इस परियोजना से प्रदेश की डेयरी प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि होगी और राज्य में ही मिल्क पाउडर बनाया जाएगा। इससे समीपवर्ती राज्यों से मिल्क पाउडर बनवाने का और लोडिंग–अनलोडिंग का खर्च कम होगा। साथ ही स्थानीय उत्पादकों को बड़े बाजारों तक पहुँच में आसानी होगी। इस परियोजना के तहत डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाएगा और निजी भागीदार द्वारा संयंत्र का संचालन, 'निर्माण–संचालन–ट्रांसफर' मॉडल पर किया जाएगा।

पोषण/प्रशिक्षण चम्पावत

चंपावत जिला मुख्यालय के गोरलचौड़ मैदान स्थित ऑडिटोरियम में ''पोषण भी–पढ़ाई भी'' अभियान के तहत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें चम्पावत विकासखण्ड की 100 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां भाग ले रही हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद बिष्ट ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को कुपोषण से लड़ने के तरीके, बचाव, बच्चों में व्यावहारिक परिवर्तन और नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर वैज्ञानिक आधार पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

स्वच्छता अभियान

चम्पावत जिले में 10 सितम्बर से 17 सितम्बर तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले के नगर पालिका क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक सहित विभिन्न प्रकार के कूड़े का निस्तारण किया जा रहा है। अभियान के तहत जिलाधिकारी मनीष कुमार ने आज लोहाघाट नगर पालिका क्षेत्र में श्रमदान और कूड़ा निस्तारित कर स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

स्काई लिफ्टर वाहन

रुद्रप्रयाग नगर पालिका को एक नए स्काई लिफ्टर वाहन की सौगात मिली है। इस वाहन का उद्घाटन जिलाधिकारी प्रतीक जैन और नगर पालिका अध्यक्ष संतोष रावत ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि स्काई लिफ्टर वाहन नगर पालिका के कार्यों को और अधिक सुगम व प्रभावी बनाएगा। विशेषकर सफाई, विद्युत मरम्मत, ऊंचाई पर रख–रखाव कार्य, होर्डिंग्स और सजावट संबंधी कार्यों में इस वाहन का उपयोग शहर की व्यवस्था सुधारने में मददगार सिद्ध होगा। नगर पालिका अध्यक्ष संतोष रावत ने कहा कि नगर पालिका रुद्रप्रयाग को ये आधुनिक वाहन मिलने से शहर के विकास कार्यों में तेजी आएगी और नगर वासियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी।